विश्वकर्मा संकेत
VISHWAKARMA SANKET

भारतीय मज़दूर संघ का मुख पत्र

Vol 13 No.3 Annual Subscription Rs. 50/-, Single Copy Rs. 5/- March, 2005

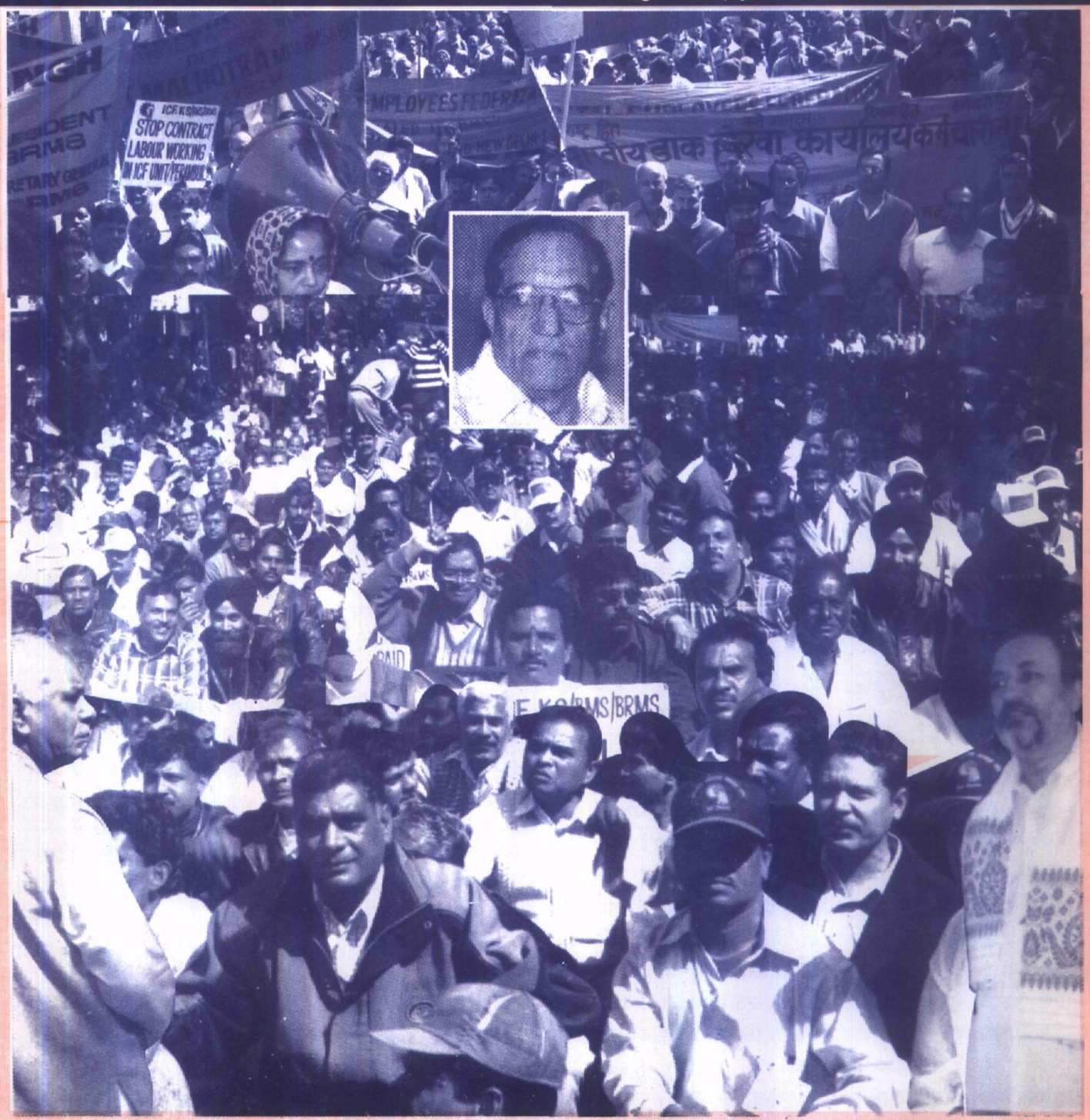

'सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ' द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में १८-फर. को जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन में सर्वश्री उदय पटवर्धन, गिरीश अवस्थी एवं विजय कुमार मलहोत्रा

बजट के मुख्य बिन्दु

- एक लाख रू. तक आमदनी आय-कर से मुक्त
- एक दिन में बैंक से १०-हजार रू. से अधिक निकालने पर ०.१% कर लगेगा
- मोबाइल आयकर रिटर्न से मुक्त ५०-हजार से अधिक का वार्षिक बिजली बिल शामिल
- राजमार्ग प्रोजेक्ट के लिए पेट्रोल व डीजल पर ५० पैसे प्रति लीटर उपकर लगेगा
- रसोई गैस ओर मिट्टी के तेल पर सीमा शुल्क नहीं, कच्चे तेल पर सीमा शुल्क घटा
- ४-लाख तक व्यवसाय करने वाले सेवा प्रदाताओं को सेवा कर से छूट
- कषि उत्पादों पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर १५%
- लोहे, इस्पात पर शुल्क घटा, कपड़ा मशीनरी, रेफ्रीजरेटेड वाहनों पर शुल्क १०%
- चयनीत पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटकर १०%
- व्यवसाय आधारित लघु उद्योगों के लिए छूट की ३-करोड़ रू. की अधिकतम सीमा बढ़ाकर ४-करोड़ रू.
- घरेलू बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को कुछ और व्यवसायिक सुविधायें
- अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लिए इक्विटी सहायता में वद्धि
- अल्पसंख्यक बहुल जिलों ब्लॉकों या गावों में स्कूल खुलेंगे
- अनिवासी भारतीयों द्वारा अर्जित ब्याज पर कर में छूट रहेगा
- २-करोड़ ३०-लाख घरों को बिजली के नये कनेक्शन
- भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलूर को विश्वस्तरीय विवि बनाने के लिए सौ करोड़ रू.

सामाजिक कर्तव्य और पत्नि धर्म में समझौता नहीं

कुछ शताब्दियों पुरानी बात है । तमिलनाडु में काँचीपुरम् के निकट 'तेल्लारू' नामक गाँव की ग्राम पंचायत की महिला सरपंच थी 'परमकरूणै' । एक बार गाँव की कुछ महिलाओं ने उनके पास न्याय के लिये गुहार लगाई । उनका कहना था कि प्रतिदिन स्नानार्थ नदी जाते समय उनके साथ एक व्यक्ति अभद्रता करता है । गाँव के कोतवाल द्वारा उस व्यक्ति को बंदी बना कर सरपंच के समक्ष लाया गया । सुनवाई के पश्चात् 'परमकरूणै' ने आगामी ४०-दिन तक उसे प्रतिदिन गाँव के शिव मंदिर प्रांगण की सफाई करके, पानी छिड़कने का दंड दिया । दूसरे दिन से ही दंड प्रारंभ हो गया । किंतु अगले दिन ग्रामवासियों ने अकल्पनीय दश्य देखा । स्वयं 'परमकरूणै' शिवमंदिर के सामने झाड़ू लगाकर सफाई कर रही थी और पानी छिड़क रही थी । चकित लोगों के प्रश्न का उत्तर दिया कि 'सरपंच के नाते मैंने कल अपराधी को दंडित करने का निर्णय दिया, वह मेरा सामाजिक कर्तव्य था, परंतु वे मेरे पति होने के कारण उनके दंड भुगतने में मुझे भी सहभागी होना मेरा पत्नि धर्म है, उसे मैं अब निभा रही हूँ '।

उसका सामाजिक कर्तव्य बोध और गहिणी धर्म निभाने में श्रद्धा - इन दोनों की सराहना करते हुए ग्रामवासियों ने उसे 'कुडिक्कुराई तीर्त्त नाचियार' (जन संकट के प्रति संवेदनशील नारी) उपाधि देकर उसी शिव मंदिर के द्वार पर शिलालेख लगवाया जो आज तलक भी वहीं दश्यमान है ।

स्व. ठेंगड़ी जी के प्रेरक प्रसंग

• पहली भेंट में ही व्यक्ति उनका हो जाता था

राजू नामक व्यक्ति का एक दिन फोन आया कि ठेंगड़ी जी से बात करनी है । ठेंगड़ी जी को बतलाते ही वे तुरंत उठकर फोन पर परिवार के सभी सदस्यों का कुशलक्षेम पूछने लगे । अंत में सायं ५ बजे पिताजी को साथ लेकर घर पर मिलने की बात तय हुई । फोन रखने के उपरांत उन्होंने मुझे कहा कि सायं ५ बजे एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है । उसको एक शाल तथा एक कुर्ता देना है तथा खाने-पीने हेतु कुछ अच्छे पदार्थ काजू, बादाम, काजू बर्फी, जूस आदि भी मंगाना होगा । प्रायः ५ बजे तक वे विश्राम किया करते थे परंतु उस दिन ४ बजे से ही वे तैयार होकर गेट के पास कुर्सी पर आ बैठे । नियत समय पर राजू अपने पिता शब्बीर मियां को साथ लेकर पहुंच गया । भेंट होते ही मा. ठेंगड़ी जी सब्बीर मियां से लिपट गये, तत्पश्चात् शाल ओढ़ाकर स्वागत करते ही शबबीर की आंखों से आंसू टपकने लगे । यह बड़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उनके बाल काटने वाला साऊथ एवेन्यू मार्किट का एक साधारण बारबर था । यानी जिस किसी छोटे-बड़े से वे एक बार मिल लेते थे सदा के लिये वह उनका हो जाता था ।

• वचन अंत तक निभाने का उनका स्वभाव

जून २००४ की बात है । मा. ठेंगड़ी जी के साथ रात्री भोजन से पूर्व साधारण बातचीत में मैंने पूछा कि आप प्रायः टैक्सी में ड्राइवर के पास ही क्यों बैठते हैं ?

उन्होंने बताया, 'इसका भी एक कारण है, डॉ. अम्बेडकर के प्रमुख सहयोगी बाबा साहिब गायकवाड़ डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती थे, एक दिन उन्हें मिलने मैं अस्पताल गया था वहां पर उनके कुछ परिवार जन भी उपस्थित थे, कुशल क्षेम पूछने पर बाबा साहिब ने मुझे पास बुलाकर कहा कि 'मेरी एक अंतिम इच्छा है और इसे तुम ही निभा सकते हो, इच्छा पूछने पर उन्होंने बताया कि जब भी तुम टैक्सी में बैठो तो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर ही बैठना'। इस प्रकार गायकवाड़ जी की इस इच्छा का उन्होंने अंत तक निर्वाहन किया । *- जगदीश जोशी कार्यालय मंत्री*

-: पाथेय :-

ना धर्मश्चरितो लोके सद्यः फलती गौरिव ।
शनैरावर्तमानस्तु कुर्तुमूलानि कृतन्ति ।।

अर्थ : किया हुआ पाप पृथ्वी में बीज की भांति तत्काल फल नहीं देता किंतु धीरे-धीरे फलित होता । अनुकूल ऋतु आने पर वह मूलोच्छेदन तक कर डालता है ।

विषय-सूची

- बजट - एक मुखौटा ५
- आर्थिक नीतियों के विरूद्ध आवाज उठाना आवश्यक ६
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस १०
- It IS Stagnating Budget 11
- TUs Reject LIC Wage Hike Offer 12
- Ordinance Sets Up Pension Regulator 15

सम्पादकीय

पेटेंट अध्यादेश लागू कर डा. सिंह ने किस का ऋण चुकाया

खुशहाली के चक्कर में उदारीकरण के विदेशी रामबाण से आहत होकर करोड़ों-२ लोग बेरोजगार हो कर पहले ही त्राहि-२ कर रहे हैं । खेती एवं कुटीर उद्योगों से जैसे-तैसे आजीविका कमाने वाले बचे खुचे लोगों पर अब नये उत्पाद पेटेंट अध्यादेश के लागू होने से गाज गिरने लगेगी । अभि-२ 'रिसर्च फाउंडेशन आफ साइंस टेक्नोलाजी एंड इकोलोजी' व 'नैशनल ग्रुप आन पेटेंटस' और 'द ट्रांस्फार्म इंडिया ग्रुप' द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी के बाद प्रख्यात् शिक्षा शास्त्री प्रो. यश पाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस अध्यादेश से किसान अपने ही बीज सुरक्षित रखकर खेती करने के परम्परागत् अधिकार से, गरीब रोगी सस्ती जीवन रक्षक औषधियों से एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी 'कम्प्यूटर साफ्टवेयर तक के उपयोग से वंचित कर दिये जायेंगे । भारतीय खेतों में कौन सी फसल उगाई जाये, इसका एकाधिकार बीज आपूर्ति करने वाले 'मोसेंटो' एवं 'कारगिल' जैसे बदनाम अमरीकी निगमों को सौंप दिया गया है, यहां तक कि अपने बीजों से खेती करने वाला कृषक दंडनीय अपराधी माना जायेगा ।

भारतीय पेटेंट विशेषज्ञ डा. बी. के. कैला ने शंका जताई कि सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी से भी कहीं अधिक गरीब रोगी अत्यंत मंहगी जीवन रक्षक औषधियों की अनोपलब्धता के कारण मृत्यु के ग्रास बन जायेंगे । ज्ञातव्य हो कि भारत गरीबों के जीवनरक्षण के अपने संवैधानिक एवं मानवीय कर्तव्य का पालन, १९७० के प्रक्रिय पेटेंट के आधार पर अत्यधिक सस्ती जीवन रक्षक औषधियों की आपूर्ति द्वारा न केवल भारत बल्कि दूसरे गरीब देशों को भी अभी तक करता आया है ।

देशवासियों को तो हैरानी इस बात की है कि WTO के जो निर्णय अमेरिका के हित में नहीं वे यदि WTO प्रणेता अमरीका के लिये ही बाध्यकारी नहीं तो अहितकर पेटेंट निर्णयों को मानना भारत अपने लिये बाध्यकारी क्यों मानता है । लोगों की तो समझ से यह भी परे है कि सच्ची सुच्ची छवि वाले डॉ. मनमोहन सिंह ने किसके दबाव में अथवा किस से वफा निभाने के उद्देश्य से गरीबों के जानलेवा उत्पाद पेटेंट अध्यादेश को बिना संसदीय चर्चा के लागू करने का साहस किया है ।

रायपुर कार्यसमिति निर्णय

१४ मार्च पेटेंट संशोधन विधेयक विरोध प्रदर्शन

रायपुर में भामसं. ने १०६वीं दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक में पेटेंट संशोधन विधेयक संसद पटल पर प्रस्तुत करने के विरोध में १४ मार्च को समूचे देश में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है । अतः धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन आदि कार्यक्रमों के माध्यम से रोष प्रकट करने का आह्वान कार्यसमिति ने समस्त देशवासियों से किया है ।

१४वां स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन - रामलीला मैदान, दिल्ली
३,४,५ अप्रैल - २००५

बैठकें - अतुल ग्रोव रोड :-

- संचालन समिति - ३१ मार्च ०५
- पदाधिकारियों सहित संचालन समिति - १ अप्रैल ०५
- कार्यसमिति - २ अप्रैल ०५
- अधिवेशन उद्घाटन प्रातः १० बजे - ३ अप्रैल ०५

श्री चन्द्रशेखर राव, श्रम मंत्री, भारत सरकार

- शोभा यात्रा प्रातः ११.३० बजे - ४ अप्रैल ०५

प्रस्थान रामलीला मैदान से जंतर-मंतर
प्रकट सभा १२-३० से २ बजे दोपहर - जंतर मंतर

- महिला सत्र ४-३० से ६.३० बजे सायं - रामलीला मैदान
- पूर्णकालिक व प्रचारक संयुक्त बैठक, भोजनोपरांत रात्री ६ बजे
- अधिवेशन समारोप दोपहर २ बजे - ५ अप्रैल ०५
- नवनिर्वाचित पदाधिकारी बैठक प्रातः ६ अप्रैल ०५

प्रस्ताव - २

कार्यसमिति द्वारा पारित पहले प्रस्ताव में जहां सरकार से मांग की है कि वह कृषकों को अपने सुरक्षित बीजों से खेती करने के परंपरागत अधिकार से वंचित कर उन्हें कारगिल एवं मोर्सेंटो जैसे बदनाम अमरीकी निगमों के हाथों गिरवी रखने वाले पेटेंट विधेयक को वापिस ले, वहां दूसरे प्रस्ताव में चिंता व्यक्त की गई कि देश के ३७ करोड़ श्रम बल में से ३० करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये पहले तो विधेयक ही देरी से वर्ष ०४ में लाया गया और लाने के बाद अभि तक भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान ही नहीं की गई । कार्यसमिति को खिन्नता इस बात की भी है कि समस्या की व्यापकता के अनुपात में GDP के मात्र १% का व्यय करने का प्रावधान न रखना तो मानो ऊंट के मुंह में जीरे के समान मजाक ही है ।

गरीबी तेरे अनेक नाम - अनुमति रिमझा

बीड़ी कामगारों के जीवन में अंधेरा

भारत में ५०% से अधिक लोग, बीड़ी, सिगार और तम्बाकू का सेवन करते हैं जिससे इनके शरीर को हानि पहुंचती है । किंतु फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं ।

दूसरी ओर इस युग में जन्में प्रत्येक मनुष्य को आजीविका चलाने के लिये श्रम करना पड़ता है, इसी प्रकार के श्रमजीवी हैं तम्बाकु की खेती में काम करने वाले, इनकी स्थिति को भी हम जानें :-

कई बार इन मजदूरों को काम करते हुए घातक रोगों से जूझना पड़ता है ।

गुजरात के खेड़ा जिले के कई गांवों में तम्बाकु की खेती होती है । जब खेती पक जाती है तब पत्तों को तोड़कर भूमि पर सूखाने के बाद इनको हाथों से तोड़कर बारीक करना पड़ता है । महिलाएं इनकी कुटाई डंडों से करती हैं । इस प्रकार जो चूरा उड़ता है वही श्वास द्वारा फेफड़ों में जाने से मजदूरों को टी.बी., कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं ।

हमारे देश में बहुत से लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं । मध्यप्रदेश तो बीड़ी बनाने का गढ़ है । कई परिवार इस काम में लगे हुए हैं । कई परिवारों का पीढ़ियों से आज तक यही धंधा है । बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को प्रायः कमर दर्द, टी.बी, कैंसर, दमा, आँखों के रोग आदि से ग्रस्त होना पड़ता है ।

वर्ष १९८६ से इन मजदूरों के लिये सरकार ने निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान तो किया है किंतु इस योजना की मजदूरों को जानकारी न होने के कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाते थे । सेवा द्वारा कई वर्षों के सघन प्रयास से अब कहीं जाकर म.प्र. के मजदूरों को इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है किंतु कई बार रोग की विकरालता के अनुपात में उपलब्ध अपर्याप्त सुविधा के कारण आज भी मजदूर को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है ।

अतः इन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं समुचित रूप से मिलें इसके लिये सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को साथ मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी समाज की कल्पना साकार हो सकेगी ।

भगवान् स्वरूप बच्चों की दुर्दशा

लाड़ प्यार की आयु में कोमलांगी बच्चों को पढ़ने की बजाये पेट भरने के लिये मजदूरी करने पर विवश होते हम सभी प्रायः देखते हैं ।

यात्रा करते एक बार मैंने देखा कि छोटे-२ बच्चे अपने पहने हुए कपड़ों को उतारकर उससे ही गाड़ी के डिब्बें में फैले कचरे की सफाई कर रहे थे और उसके बाद यात्रियों से मजदूरों के रूप में नहीं बल्कि भीखारियों के समान पैसे मांग रहे थे ।

प्रातः होते ही मैंने देखा कि छोटे-२ बच्चे समाचार पत्र बेच रहे हैं, कुछ बच्चे यात्रियों का सामान ढो रहे हैं तो कुछ बच्चे चाय बेच रहे हैं । ऐसा क्यों ? इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं जो उन बच्चों को ये सारे काम करने पर विवश कर रहीं हैं ? इसके पीछे उनका परिवार हो सकता है । उनके माँ-बाप खेल-कूद की बजाये स्वयं उन्हें मजदूरी करने भेजते होंगे क्योंकि उनको भी निश्चय ही कोई आर्थिक परेशानी होगी । वैसे तो बच्चों को भगवान् का रूप माना जाता है फिर भी हमारे देश में इन भगवान् स्वरूप बच्चों की ऐसी दुर्दशा क्यों है ? इनकी इस स्थिति के लिये सरकार भी थोड़ी बहुत तो जिम्मेदार है ही । वैसे अब तो सरकार भी कुछ चेती है और उसने बच्चों से इस प्रकार मजदूरी करवाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना प्रारंभ किया है ।

बच्चों की इस स्थिति के पीछे एक और शक्ति जिम्मेदार है वह है हमारे देश की गरीबी । जो माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वे भी गरीबी के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं, ताकि उनका बच्चा भी रोजी कमाने में उनके साथ हाथ बटा सके ।

बाल मजदूरी के विरूद्ध सरकारी कानून बनाये जाने के बाद भी बाल मजदूर घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं ।

ईश्वर रूपी इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए क्योंकि उनकी आंखों में भी कुछ सपने हैं, मन में इच्छाएं हैं, वे पूरी नहीं हो पातीं । बच्चे तो कोमल पौधों के समान होते हैं पुष्पित पल्लवित करके उन्हें सभ्य नागरिक के रूप में विकसित किये बिना, हम अपने नैतिक एवं सामाजिक ऋण से मुक्त नहीं हो सकते ।

('अनसूया' मासिक पत्रिका से साभार)

सांस्कृतिक वैभव बिना आर्थिक प्रगति अर्थहीन - *शेखावत*

उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत ने कहा है कि यदि हम केवल आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ गए और सांस्कृतक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ कर अपने संस्कार भूल गए तो हमारा विकास अधूरा रहेगा ।

वरिष्ठ टेलीविजन प्रोड्यूसर बृजेंद्र रेड्डी द्वारा निर्मित टेलीविजन कार्यक्रम 'समय का साक्षी' का अवलोकन करने के पश्चात् उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी और देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें प्रत्येक नागरिक न केवल आर्थिक दृष्टि से सक्षम व आत्मनिर्भर हो बल्कि देश की समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का वाहक बने ।

इस अवसर पर पूर्व एयरमार्शल अर्जन सिंह, सांसद राजीव शुक्ला जाने-माने साहित्यकाल विष्णु प्रभाकर, अशोक वाजपेयी सहित अनेक पत्रकार एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

केन्द्रीय कार्यालय से.....

अमर नाथ डोगरा,
मंत्री, भामसं.

बजट – एक मुखौटा

केन्द्रीय बजट वर्ष २००५-०६ संसद में प्रस्तुत करते समय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के मन में जो भी रहा हो किंतु प्रकटतया इस की प्रस्तुति के प्रति आंतरिक प्रतिबद्धता का अभाव उनके चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता था । विनिवेश आर्थिक सुधार आदि विषयों को बजट में ज्यादा स्थान नहीं दे पाने के कारण कदाचित् वह असहज हुए हों किंतु बहु राष्ट्रीय एवं देशी कंपनियों को करों में मन माफिक छूट प्रदान करके उन्होंने अपना सहज स्वाभाविक खेल खेला है और परिणामस्वरूप उद्योग जगत व पूंजीशाह गद्‌गद् हैं । शेयर मार्केट में सैन्सैक्स की ऊँची उड़ान इसका प्रमाण है ।

उपरोक्त के बावजूद अगर वित्त मंत्री जी अपनी फुल फार्म में न दिखे हों तो इसका वास्तविक कारण वही जानते होंगे पर हमारा अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व विश्व व्यापार संगठन जिस प्रकार पेटेंट संशोधन अध्यादेश २००४ और इसे ही अब १४ मार्च २००५ को विधेयक के रूप में वाणिज्य मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत करवाने में सफल हुए हैं । इसी प्रकार श्रम कानूनों में सुधार स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र निर्माण और अन्य अनेक संबंधित सुविधाओं का प्रावधान किए जाने की अपेक्षा वह वित्त मंत्री जी से भी चाहते होंगे और वित्त मंत्री जी स्वयं भी इसी प्रकार की अर्थ रचना अपने बजट द्वारा करना चाहते होंगे पर गठबंधन की सरकार के चलते कर नहीं पाए । अतः बजट प्रस्तुत करते समय अपनी पूरी रंगत में नहीं रह पाए ।

सच्चाई मगर यह है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े दीन, हीन, निर्धन जन को ध्यान में रख कर आज तक कोई भी बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया । बजट प्रचारित तो साधारण जन के नाम पर होता है किंतु सुविधाओं के प्रावधान समाज के उच्च वर्ग के लिए होते हैं । स्वतंत्रता के पश्चात् अमीर और अमीर व गरीब और गरीब हुआ है क्योंकि बजट वास्तव में उच्च वर्गीय केवल २० प्रतिशत जनता के लिए होता है शेष ८० प्रतिशत अभावग्रस्त, भुखमरी, अशिक्षा व रोगग्रस्त जनता के लिए वायदों के छलावों के अतिरिक्त बजट में कुछ नहीं होता ।

बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने भारत निर्माण अथवा 'भारत बनाओ' परियोजना का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत ढांचागत् सुविधाओं यथा सड़क बिजली, पेयजल व कृषीआदि के लिए प्रावधान किए गए हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं किंतु घोषणाएं तो १९७१ में 'गरीबी हटाओ' के अंतर्गत भी बहुत की गई थी । परिणाम हमारे सामने है । गरीबी यथावत् है पर उद्‌घोषक उपरोक्त नारे की नाव पर बैठकर सत्ता सुख की वैतरणी आराम से पार कर गए । उसी परंपरा में 'भारत बनाओ' नाम से काठ की हांडी फिर चढ़ा दी गई है पर जनता अब जागरूक है और किसी छलावे में आने वाली नहीं है ।

केन्द्र की सरकार न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के आधार पर चल रही है और इस कार्यक्रम के जनक वामपंथी दल हैं । वामपंथी दल और उनके श्रम संगठन एक मेक ही होते हैं अतः वामपंथी श्रम संघों से हम जानना चाहते हैं कि आयात पर कस्टम ड्यूटी घटाते समय निर्यात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया । उद्योगों को करों, उत्पाद शुल्क आदि में राहत प्रदान की गई किंतु कामगारों को प्राप्त स्टैण्डर्ड डिडक्शन्ज की राहत छीन ली गई । भविष्य निधि ब्याज दर बढ़ोत्तरी (९.५%) को हरी झंडी नहीं दिखाई गई । बोनस पर सीलिंग नहीं हटाई गई । छठे वेतन आयोग गठन की घोषणा नहीं की गई । आयकर सीमा दो लाख नहीं की गई । एक लाख तक सीमा बढ़ाई गई किंतु मानक कटौती विशेषकर बीमा व भविष्य निधि जमा राशि प्राप्त राहत वापिस लेकर आयकर सीमा बढ़ोत्तरी के लाभ को निरस्त कर दिया गया । डीजल व पैट्रोल पर सैस लगा देने के कारण उपभोक्ता एवं अन्य इंस्तेमाल की सभी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे । मंहगाई पहिले ही आसमान छू रही है, उसमें और वृद्धि होगी । मंहगाई को काबू करने का कोई कदम उठाया नहीं गया है । विदेशी निवेश के लिए दूरसंचार, बीमा, बैंक, उड्डयन व निर्माण आदि क्षेत्र तो खोले जा चुके थे । अब उत्खनन एवं व्यापार आदि भी खोल दिए गए हैं । प्रकारांतर और कालांतर से अन्य अनेक क्षेत्र भी देर सवेर खोल दिए जाएंगे । स्पष्टतया विश्व व्यापार संगठन का दबाव इसमें काम करता हुआ दिखाई देता है किंतु हमारे वामपंथी दोस्त किस दबाव के तहत इस हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं ।

बजट की बहार तो लूटेंगे नव धनाढ्य व उच्च वर्ग और मार खाएगा निर्धन वर्ग । इसका स्पष्ट प्रमाण है वह प्रावधान जिसके तहत एक दिन में १०,०००/- की राशि बैंक से निकलवाने पर १०/- का टैक्स भरना पड़ेगा । इसकी सीधी मार छोटे खाताधारियों पर पड़ेगी । जमा ब्याज दर में बढ़ोत्तरी की कुछ क्षीण से अपेक्षा की जा रही थी उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई, फलस्वरूप लघु बचत प्रवृत्ति का हतोत्साहन ही होगा ।

रोजगार सृजन की थोथी घोषणाएं हैं । एक अनुमान के अनुसार असंगठित क्षेत्र में ही लगभग २२ करोड़ बेरोजगार हैं । शहरी क्षेत्रों में लगभग चार करोड़ रोज़गार केन्द्रों में पंजीकृत हैं । पचास बड़े नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग दो करोड़ युवा रोजगार की तलाश में झुग्गी, झोपड़ी, बस्तियों में रह रहे हैं । इन सबके लिए रोजगार का प्रबंध कैसे होगा । केवल वस्त्रोद्योग को पुर्नजीवित या पुर्नगठित कर देने से

करोड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता

शेष पृष्ठ १० पर

आर्थिक नीतियों के विरूद्ध आवाज उठाना आवश्यक - *चन्द्रशेखर पूर्व प्रधनमंत्री*

WTO की बैठकों से लौटने के बाद हमारे मंत्रिगण देश को समझाते हैं कि उन्होंने कितने परिश्रम से देश के हितों की रक्षा की । हो सकता है कि वे प्रामाणिकता से इसके लिए प्रयास करते भी हों किंतु परिणाम तो उलटा ही दिखाई देता है । करोड़ों रोजगार छीनने वाली उदारीकरण की त्रासदी से देश अभि उबरा भी नहीं था कि पेटेंट के नये फंदे में फंसकर कुटिर और लघु उद्योगों से रोजी कमाने वाले करोड़ों-२ लोगों को भूखे मारने का षड़यंत्र रचा जा रहा है । पेटेंट संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में जो आश्वासन आज के रक्षामंत्री (तत्कालीन वाणिज्य मंत्री) प्रणव मुखर्जी देकर आये थे उनका परिणाम हमारे सामने है । १६७० के पेटेंट कानून को आमूल-चूल बदलकर हम ऐसे जाल में फंस रहे हैं जो हमें हमारी हजारों वर्षों से संजोयी प्राकृतिक संपदा को दूसरे के हाथ में देने को विवश कर देगा । हमारे देश के मूर्धन्य वैज्ञानिक यह मांग कर रहे हैं कि पेटेंट कानूनों में इसकी व्यवस्था की जाए कि किसी उत्पाद के स्रोत को सुरक्षित रखने वाले को भी लाभ मिले परंतु विदेशी सरकारें इस पर सहमत नहीं हो रही हैं । प्रक्रिया और उत्पादन दोनों का ही पेटेंट औषधियों के दाम में अत्याधिक वृद्धि करेगा । इस पर सभी एकमत हैं । फिर हम क्यों इतने उतावले हैं कि संसद में पेटेंट बिल-२००३ के लंबित रहते हुए भी नये अध्यादेश लाने के लिए विवश हुए ? यह जानते हुए भी कि हमें इस समस्या से निपटना पड़ेगा । हमने विभिन्न क्षेत्रों में शोध की दिशा में क्या काम किया ? वर्तमान की राजनीति में उलझे राजनीतिज्ञों से तो यह आशा करना कि वे इन दूरगामी नीतियों पर विचार करेंगे एक मृगतृष्णा ही है, परंतु जो लोग अपने को देश के उज्जवल भविष्य का राजनेता समझते हैं उन्होंने इसकी अभी तक क्यों उपेक्षा की ।

बहुत पहले चाणक्य ने कहा था कि अर्थनीति ही राजनीति का आधार है । आज भी वह अक्षरशः सत्य है । यह अर्थनीति किन के हित में काम करेगी यही आज की राजनीति का मुख्य मुद्दा है । जो लोग या जो दल जनोन्मुखी राजनीति करना चाहते हैं या करने का दावा करते हैं उन्हें बिना सोचे-समझे आरंभ की गई इन नीतियों के विरूद्ध एकजुट होकर अविलंब आवाज उठाने की आवश्यकता है ।

डा. कलाम का देश के शासकों से पेटेंट आलेखों के संरक्षण का आग्रह

भारत के राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत के वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि भारत की समृद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वे आगे आयें और नवीनतम तकनीकी का उपयोग कर ऐतिहासिक साक्ष्यों की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाएं । उन्होंने स्मरण दिलाया कि भारत को पूर्व में बासमती, नीम और हल्दी जैसे पारम्परिक प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गुहार लगानी पड़ी थी । ऐसी समस्याएं भविष्य में बढ़ने वाली हैं । इस दृष्टि से अपने देश में ही परंपरागत् ज्ञान पद्धति, बीज औषधीय पौधे एवं खाद्यान्न के अतिरिक्त विशाल प्राकृतिक संपदाओं का प्रमाणिक आलेखीकरण एवं उसके आंकड़े एकत्रित करने होंगे और इन महत्वपूर्ण आलेखों की सुरक्षा का भार कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि संग्रहालय को संभालना चाहिए । उन्होंने कहा कि विज्ञान भारत के किसानों के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । WTO में किसानों के हितों की रक्षा हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु तैयार रहना चाहिए ।

जानने योग्य तथ्य

- शिक्षा को रचनात्मक बनाना समय की मांग है
  - राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
- वर्तमान समय में हस्तशिल्प उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ऐसे कुशल हस्तशिल्पी हैं तो विश्व स्तर पर पहचान बना सकते हैं
  - भैरो सिंह शेहरावत, उपराष्ट्रपति
- हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ी के चलाने से एक कृषक परिवार के लिये आवश्यक दैनिक बिजली उत्पादन करने में सफलता प्राप्त कर ली है
  - वैज्ञानिक, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अभि तक हुए पेटेंटों का 'अंकटाड' सर्वेक्षण

- 'अंकटाड' द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ५-विकसित राष्ट्रों के नागरिकों के पास विश्वभर के ६५.६%, समाजवादी यूरोपीय राष्ट्रों के पास ३.४%, दक्षिण यूरोप के पास ०.४% और विकासशील देशों के पास मात्र ०.६% पेटेंट हैं
- नाइजीरिया जैसे देश में तो दिये गये पेटेटों में से ६८.५% विदेशियों के पास हैं जिनमें से ७७% अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पास हैं
- प्रायः विकासशील देशों में भी लगभग ८०% तक पेटेंट विकसित राष्ट्रों के नागरिकों अथवा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं
- पेटेंट प्राप्ति के लिये अमरीकी निगमों को प्रायः २५ करोड़ डालर खर्च करने पड़ते हैं
- प्रख्यात कीथ मास्कस के अनुसार अमरीका को पेटेंट की रायलटी की आय ही अनमानतः २५ बिलियन डालन वार्षिक है
- वस्तुतः पेटेंट व्यवस्था अमरीकी लूट का एक कानूनी तरीका है ।

सर्वोच्च शासक की आदर्श-प्रियता प्रत्येक व्यक्ति के

पुण्य स्मरण

साम्प्रदायिक सौहार्द्य के अमर बलिदानी गणेश शंकर विद्यार्थी

इलाहाबाद के अतरसुइया मुहल्ले में अपने नाना सहायक जेलर सूरज प्रसाद के घर जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी तपः स्थली कानपुर में ही २५ मार्च १६३० को हिन्दू मुस्लिम सौहर्द्य अक्षुणन बनाये रखने के लिये पहला बलिदान देकर इस नगरी को गौरव प्रदान किया है ।

'सर्वपंथ समादर मंच' प्रतिवर्ष गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस २५ मार्च को देशभर में धूम-धाम से मनाकर साम्प्रदायिक सौहार्दय के सूत्र को सुदृढ़ बनाने में प्रयासरत् है । इस अवसर पर विद्यार्थी जी की संपूर्ण जीवन झांकी हम सभी के लिये निश्चय ही प्रेरणादायी रहेगी । इनके पुरखा 'हथगांव' जनपद फतेहपुर के निवासी थे किंतु जीवन यापन के लिये उनके पिता ज्योतिष के विद्वान जय नारायण अध्यापक बनकर ज्योतिष का धंधा म.प्र. के 'गंगवली' कस्बे, गुना जनपद में करने लगे तथा पुत्र गणेश को स्थानीय एंग्ले वर्नैक्यूलर स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया । बाद में अपने बड़े भाई के पास कानपुर आकर क्राइस्ट चर्च कालेज से १०वीं परीक्षा इन्होंने पास कर ली । तदंतर इलाहाबाद आकर इन्टर में प्रवेश तो ले लिया किंतु पढ़ाई बीच में छोड़कर 'हरवंश पुर' जनपद इलाहाबाद में कुमारी चन्द्र प्रकाश के साथ उन्हें विवाह सूत्र में बंधना पड़ा । तभी से विद्यार्थी जी का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ एवं नौकरी के लिये पुनः भाई के पास कानपुर आ गये । १६०८ में रिज़र्व बैंक के क्रेंसी विभाग में ३० रू. मासिक की नौकरी तो मिल गई किंतु इसे छोड़ १६०६ में पी. पी. एन. हाईस्कूल में अध्यापन कार्य लग पड़े । इसे भी अधिक समय नहीं किया । बाद में इलाहाबाद में 'सरस्वती' एवं 'अभ्युदय' पत्रों के संपादन में भी काम किया किंतु कुछ समय बाद अस्वस्थ होकर पुनः कानपुर लौट आये और यहां से आपने १६ नवं. १६१८ से नये साप्ताहिक पत्र 'प्रताप' का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया ।

'प्रताप' को बेजोड़ प्रकाशन बनाने के लिये विद्यार्थी जी को कम्पोजिंग, मशीन छपाई एवं पत्रिका के बाह्य वितरण तक में स्वयं को खपाना पड़ा । परिणाम स्वरूप पत्रिका की दिनोंदिन बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी शासक के पांव लड़खड़ाने लगे । १६२० से जैसे ही 'प्रताप' साप्ताहिक से दैनिक हुआ तो प्रशासन ने प्रकाशन के सातित्य में बाधा डालने के उद्देश्य से विद्यार्थी जी को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया और भारी आर्थिक दंड भुगतान करने पर भी विवश कर दिया ।

समझौता करने की बजाये विद्यार्थी जी का स्वर अधिक प्रखर होने लगा । स्वाधीनता आंदोलन में विद्यार्थी जी की प्रतिभागिता निर्भीकता से होती थी । क्रांतिकारियों की सहायता, उनके परिवारों का भरण पोषण और स्वयं उनके समान ही आंदोलन करने में सदैव अग्रसर वे रहते रहे थे । शहीद भगत सिंह की योजना पूर्णरूपेण सफल हो इस दृष्टि से उन्हें अपने पास रखकर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते रहने वाले थे हमारे गौरव गणेश शंकर विद्यार्थी ।

'विश्वकर्मा संकेत' अंग्रेजी/हिन्दी मासिक पत्रिका
स्वामित्व एवं अन्य ब्यौरा (फार्म-४, ब्यौरा-८)

१.	प्रकाशन का स्थान	: राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली - ५५
२.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
३.	मुद्रक का नाम	: मै. जुपिटर प्रिंटर्स, १३६-बी, ईस्ट मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - ७
४.	प्रकाशक का नाम	: उदय पटवर्धन, राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली - ५५
५.	सम्पादक का नाम	: प्रेम नाथ शर्मा, राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली - ५५
६.	नागरिकता	: भारतीय
७.	स्वामित्व	: भारतीय मजदूर संघ, राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली - ५५

मैं उदय पटवर्धन घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है ।

दिनांक १.३.२००५ हस्ता./-
उदय पटवर्धन

न्यायालय निर्णय

उद्योग बंदी की राज्य सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक

औद्योगिक संबंधों पर संभवतः प्रभाव डालने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी औद्योगिक इकाई को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बंद नहीं किया जा सकता, भले ही उसका प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन उस संबंध में कोई समझौता ही क्यों न कर लें ।

न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े और न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा की उच्चतम न्यायालय खंड पीठ ने कहा कि औद्योगिक विवाद कानून की धारा-२५ एन और २५ओ में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी नियोक्ता औद्योगिक इकाई को बंद करना चाहता है या फिर कर्मचारियों की छंटनी करना चाहता है, उसे ऐसा पग उठाने के कम से कम ६० दिन पहले राज्य सरकार से अनुमत प्राप्त करनी होगी ।

दिहाड़ी मजदूर को नियमितीकरण का अधिकारी नहीं

नौकरी के नियमितीकरण के अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े व के. एन. सिन्हा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कीम के तहत कोई श्रमिक दिहाड़ी वेतन के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो उसे सेवा के नियमितीकरण के लिए कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता है । न्यायालय ने अपनी महत्वपूर्ण व्यवस्था में कहा है कि यदि श्रमिक की नियमानुसार नियुक्ति नहीं होती है, तो एक वर्ष में २४० दिन लगातार कार्य करने के आधार पर उसकी सेवा नियमित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता ।

निर्माण मजदूरों को म.प्र. में ५० से ४५० रु. मासिक छात्रवृत्ति

म.प्र. श्रममंत्री हरनाम सिंह राठौर ने निर्माण श्रमिकों के दो बच्चों अथवा पत्नि सहित एक बच्चे को शिक्षा स्तर के अनुसार ५० रू. से ४५० रू. मासिक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है । छात्राओं को छात्र से ५० रू. अधिक मिलेगा । गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रही ३५ वर्ष से कम आयु की जो श्रमिक पत्नि किसी शिक्षण संस्था की नियमित छात्रा हो वह भी इस सुविधा की अधिकारी होगी । वार्षिक ३-किश्तों में छात्रवृत्ति का भुगतान अक्तूबर, जनवरी एवं जुलाई मास में किया जायेगा । अपंग छात्रवृत्ति का लाभ पाने वाले विकलांग छात्रों को भी नियमानुसार इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा ।

(म.प्र. श्रम कल्याण मासिक पत्रिका)

भारत ने अमरीकी अधिकारी की नियुक्ति को स्वीकारा

अमरीका द्वारा दी जाने वाली संवेदनशील उच्च प्रोद्योगिकी के प्रयोग पर देखरेख रखने के लिये भारत सरकार ने अमरीकी अधिकारी की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है । भारत-अमरीका उच्च प्रोद्योगिकी सहयोग समूह की समीक्षा बैठक के बाद भारत यात्रा पर आये अमरीकी वाणिज्य उपमंत्री केनेथ जस्टर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 'इस नियुक्ति को गंभीरता से लेने से बचना चाहिए' ।

गत २-वर्षों में गुजरात रोजगार सृजन में प्रथम

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षि विवरण के अनुसार सार्व. एवं निजि क्षेत्र में मार्च से अक्तू. २००४ के मध्य मात्र ८-मास में १-लाख, ३२-हजार ७१-बेरोजगारों को सर्वाधिक गुजरात राज्य में नौकरी मिली है । इस बीच उद्योगिक घरानों के सहयोग से उद्योगिक भर्ती मेलों के आयोजन से १-लाख, ३२-हजार, ३-सौ ५०-लोगों को रोजगार मिला । इसमें सरकारी व सेना में मिले रोजगार शामिल नहीं हैं । राज्य के सभी २५-जिलों में सरकार ने जी-स्वान इन्फोर्मेशन टैक्नोलाजी नैटवर्क पर आधारित आन लाइन कनेक्टिविटी वाली प्रशिक्षण रोजगार नियामक की विशेष वेबसाइट चालू कर रखी है जिससे बेरोजगारों का आनलाईन पंजीकरण और डेटाबेसका दैनिक नवीनीकरण होता है । जिससे सार्व. व निजि उपक्रमों से बेरोजगारों का जीवंत सेतु स्थापित हो जाता है । रोजगार उन्मुख युवको को प्रेरित व प्रशिक्षित करने की राज्य ने प्रभावी व्यवस्था की है । गत् ३-वर्षों में सेना की भर्ती भी ३-गुना बढ़ी है । वर्तमान की उद्योगिक कुशलता के अनुरूप छात्रों के योग्य प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों एवं उद्योग गृहों का एक मंच स्थापित करने और स्कूल टू स्किल योजना भी राज्य सरकार ने चालु कर दी है ।

अमरीकी अक्षत उपग्रह – भारतीय प्रतिभा का सम्मान

भारत के जयपुर वासी एक प्रतिभाशाली छात्र अक्षत सिंघल के नाम पर आकाशीय एक उपग्रह का नाम १२५७७ 'सिंघल' रखकर अमेरिका के मैस्यूच्चुस्टेट इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी (एम.आई.टी.) तथा लिंकन लेबोरेट्री ने इस प्रतिभावान् छात्र को सम्मानित किया है । इस होनहार अक्षत ने अमेरिका में आयोजित इन्टरनैशनल सांयस के नाम पर एक इंजीनियरिंग मेले में साफ्टवेयर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था । इस छात्र के नाम से जाना जाने वाला उपग्रह ब्रह्मांड के मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है । यह सचमुच हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है ।

जल संयंत्र से सस्ते बिजली उत्पादन यंत्र को पेटेंट मिला

अहमदाबाद निवासी घनश्याम भाई पटेल के अविष्कृत यंत्र से २३१ कि.मी. गुजरात में निरंतर बहने वाले नर्मदा जल प्रवाह से ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा । यह प्रदूषण रहित एवं खर्चा मात्र १.५० रू. प्रति यूनिट होगा । इतना ही नहीं तो गुजरात के १६-सौ कि.मी. तक फैले समुद्री तट पर भी इस यंत्र द्वारा ६०-७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा । भारत सरकार के पेटेंट विभाग ने इसे पेटेंट प्रदान कर दिया है । इस यंत्र का कार्यकाल ३० से ५० वर्ष तक का हो सकता है । समुद्र में तैरते हुए जहाज के समान स्थापित यह विद्युत उत्पादन यंत्र समुद्री लहरों के बल से निरंतर बिजली उत्पादन कर सकता है । यंत्र की देखरेख के अतिरिक्त अन्य मानवीय सहायता इसमें नहीं लगती । अमरीका व अन्य २४-यूरोपीय देशों में भी पेटेंट मिलने की संभावना है । जल प्रवाह यंत्र के प्लेयर धक्के से यंत्र चलने लगता है, इसीसे अंदर का ही क्रियेशन गेयर ७५० से ३-हजार चक्कर प्रतिमिनट की गति से चलने लगता है जिससे विद्युत उत्पन्न होने लगती है । इसमें न तो बांध ही बांधने पड़ते हैं और न ही बस्तियों को उजाड़ना पड़ता है । कई प्रदेशों ने इस यंत्र में रूचि दिखाई है ।

भारतीय मजदूर संघ ने आर्थिक सहायता नकारी

'चायना फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस' द्वारा सुनामी पीड़ित सहायतार्थ भारतीय मजदूर संघ को देने हेतु नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को भेजी ५०-लाख रू. की सहायता राशि के आग्रह को धन्यवाद सहित यह कहते हुए लेने से नकार दिया है कि हम अपने देशवासियों की सहायता करने में स्वयं सक्षम हैं ।

ILO अनुदान से बाल श्रमिक विकास का प्रस्ताव

अन्य गरीब देशों के समान भारत में भी वर्षो से बड़े श्रम संघों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर ILO बाल श्रमिक विकास कार्यक्रम आयोजित करवाता आ रहा है इसी क्रम में इस वर्ष भारतीय मजदूर संघ को भी २८-लाख रू. देने के ILO प्रस्ताव को भी लेने से यह कहते हुए नकार दिया है कि संगठन की नीति आर्थिक सहायता लेकर किसी प्रकार के भी कार्यक्रम आयोजित करने की नहीं है, संगठन, मजदूर हित में केवल सहायक हो सकता है ।

बायें से दायें : आनंदी लाल जोशी, मांगी लाल पोरवाल, एस. एन. देशपांडेय, के. जी गोस्वामी, अख्तर हुसैन, सुंदर सिंह शक्रवार एवं सम्मानित केशव लाल गुप्ता

केशव लाल गुप्ता बिजली बोर्ड से सेवा निवृत्त, भामसं. से नहीं

• **उज्जैन :** ३४वर्षीय सेवा निवृत्ति के अवसर पर, संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता श्री केशव लाल गुप्ता द्वारा श्रमिक क्षेत्र की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए समारोह के अध्यक्ष म.प्र. के श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री सुन्दर सिंह शक्रवार ने कहा कि वे विद्युत मंडल से निवृत्त हो रहे हैं किंतु भारतीय मजदूर संघ एवं विद्युत कर्मचारी महासंघ से नहीं अतः अब वे अपनी संपूर्ण शक्ति मजदूर कल्याण के लिये लगा सकेंगे । इसी प्रकार के उद्‌गार प्रकट करने वालों में महापौर श्री मदन लाल ललावत, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री मोहन लाल यादव, मुख्य अभियंता श्री के. जी. गोस्वामी के अतिरिक्त प्रदेश तथा महासंघ पदाधिकारी सर्वश्री मांगी लाल पोरवाल, भगवान दास गौंडाने, सुरेश शर्मा, एस. एन. देशपांडेय व अख्तर हुसैन मुख्य थे । भारी संख्या में प्रशंसक समारोह में उपस्थित रहे ।

बायें से उमाशंकर गुप्त, कप्तान सिंह, मु. मंत्री बाबू लाल गौर, वामनराव खेडकर एवं चेतन आर. देसाई

परिवहन महासंघ की म.प्र. मुख्यमंत्री से गुहार

• **भोपाल :** वर्षों तक लाभ अर्जित करने वाला म.प्र. राज्य परिवहन आज प्रशासनिक अव्यवस्था से पनपे भ्रष्टाचार के कारण घाटे का उद्योग बनकर बंदी के कगार पर पहुंच गया है । ११ हजार निगम कर्मचारियों को राज्य सरकार VRS देकर इस उद्योग का निजिकरण करने जा रही है ।

इसके विरोध में भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ अध्यक्ष श्री वामन खेड़कर के नेतृत्व में २०-सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री बाबू लाल गौर मु.मंत्री से भेंट कर, प्रशासनिक दोष का दंड कर्मचारियों को दिये जाने के दुष्परिणामो से अवगत करवाया ।

एक घंटा चली वार्ता के बाद मु.मंत्री ने जांच दल गठित करने एवं रिपोर्ट मिलने तक राज्य परिवहन निगम की बंदी के निर्णय को निरस्त रखने का आश्वासन दिलाया । शिष्ट मंडल में भामसं. मंत्री श्री के. लक्ष्मा रैड्डी एवं महासंघ महामंत्री श्री चेतन देसाई मुख्य थे ।

नाम गुप्त रखने की शर्त पर आंगनवाड़ी बहनों ने व्यथा सुनाई

• **कोटा :** कोटा संभाग के सभी १० जिलों से एक हजार से अधिक आंगनवाड़ी बहिनों ने ४-घंटे की बजाये १२-घंटे काम करवाने, सुविधायें उपलब्ध करवाने के नाम पर ठेंगा दिखाने, १०-नसबंदी का लक्ष्य पूर्ण नहीं करने पर वेतन कटौती व नौकरी से हटाने तक का भय दिखाने, एम.ए.वी.एस. शिक्षित कर्मचारी तक को १५-वर्षीय सेवा काल में भी पर्यवेक्षक तक भी पदोन्नत नहीं करने, आंगनवाड़ी भवन किराया तक समय पर भुगतान न करने जैसे अकल्पनीय आघातों को वर्षों तक सहने पर भी निलंबन के भय से नाम गुप्त रखने के आश्वासन पर प्रतिभागी बनी कुछ बहनों ने सहमे-२ अपनी करूण कथा का बखान किया ।

अधि. का विहंगम दृश्य

मु. अतिथि संसदीय सचिव ओम बिरला ने पसीज कर, वेतन वृद्धि एवं अन्य न्यायोचित मांगो के लिये कमेटी गठित करने का आश्वासन दिलाया । दो दिवसीय इस अधि. का उद्‌घाटन संगठन मंत्री श्री ओम प्रकाश अग्घी ने किया । अन्य संबोधन करने वालों में सांसद श्री रघुवीर सिंह कौशल, महासंघ महामंत्री सुश्री सुचित्रा महापात्र एवं प्रदेश महामंत्री श्रीमती शशी शर्मा मुख्य थे । सरकार से की गई मांगों में ५८ वर्षीय आयु होने पर सेवा निवृत्ति के अवसर पर आंगनबाड़ी कर्मियों को १-लाख रू. देने का भी आग्रह किया गया है । नगर में अनुशाषित भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई ।

'भेल' पूंजी विनिवेश विरोधी ज्ञापन राष्ट्रपति को

• **भोपाल :** राष्ट्र के कुल विद्युत उत्पादन का ७०% करने वाला, वर्ष ७२ से निरंतर लाभ अर्जित करने के साथ-२ विभिन्न सामाजिक दायित्वों के निर्वाहन करने वाला यहां तक कि अभि

शेष पृष्ठ १० पर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ८ मार्च

सर्वप्रथम १९०९ में अमरीका ने मनाया

महिलाओं को अधिकार मिले, इसके पहले उन्हें अपने लिए एक विशिष्ट दिन मिलना चाहिए । सबसे पहले वर्ष १६०६ में अमरीका में राष्ट्रीय महिला दिवस दर्ज किया गया । इसके एक वर्ष बाद, कोपनहेगन में एक बैठक में, महिला दिवस की स्थापना हुई, जिससे 'महिला अधिकारों के अभियान को सम्मान प्राप्त हो तथा उन्हें सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त होने में सहायता मिले ।' इसके एक वर्ष पश्चात्, १६११ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) पहली बार यूरोप भर में मनाया गया, जिसमें काम के अधिकार, व्यवसायिक प्रशिक्षण व भेदभाव समाप्त किये जाने की मांग की गयी ।

१६११ की घटना पर इसके संयोजकों ने गंभीर टिप्पणियां कीं, इनमें से एक एलेक्सेण्ड्रा कोलोनताई ने कहा, इस दिवस ने 'सभी की अपेक्षाओं को बढ़ाया है । जर्मनी और आस्ट्रिया ... आंदोलित हो रहे हैं, महिलाओं का समुद्र आलोड़ित हो रहा है । सभी स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, छोटे नगरों और गावों तक में महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षा से कहीं अधिक रही, यहां तक कि आयोजित गोष्ठियों में पुरूष सदस्यों को महिलाओं के लिए स्थान छोड़ना पड़ता रहा । बदले इस परिदृश्य में पत्नियों के स्थान पर पुरूषों को बच्चों सहित घर की देखभाल करते रहना पड़ा जबकि महिलायें कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर शामिल होती रहीं ।

१६१७ में कोलोनताई और जर्मन सोशलिस्ट क्लारा जैटाकिन, दोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग में ८-मार्च को आयोजित पहले IWD में भाग लिया । नई सोवियत सरकार की मंत्री होने के नाते कोलोनताई ने लेनिन पर दबाव बनाया कि 'ओजस्वी महिला श्रमिकों' का सम्मान करते हुए ८-मार्च को सरकारी कम्यूनिस्ट अवकाश के रूप में मनाया जाये । फलतः इस दिन को मान्यता मिलती गयी । विश्व में इस दिन आंदोलन किये जाने लगे । दिसं. ७७ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'महिला अधिकारों व अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित करने हेतु' सदस्य देशों को आमंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया ।

आज विश्व भर में IWD के उपलक्ष्य में पद यात्रा एवं रैलियां आयोजित की जाती हैं । वर्ष १६०६ में हुआन सोमाविया के ILO महानिदेशक पद संभालने के पश्चात् ILO ने भी इसे उत्साह पूर्वक मनाया प्रारंभ कर दिया । श्री सोमाविया ने IWD संचालन निकाय का विशेष सत्र बुलाया और इस बात का संकल्प लिया कि संगठन स्त्री-पुरूष मुद्दों पर अपने प्रयासों की 'गति बढ़ाएगा' तथा ILO द्वारा कैलेंडर में ८-मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया । तब से विश्व विख्यात कई महानुभवों के समर्थन से अपने मानवाधिकारों के लिए आगे बढ़ती महिलाओं का स्वर - सब दूर अधिक गुजायमान हुआ है ।

(ILO पत्रिका श्रम की दुनिया से साभार)

पृष्ठ ५ का शेष...

है क्या । गत् बजट जुलाई ०४ से दिसंबर ०४ तक केवल १-लाख ३-हजार बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार उपलब्ध करा सकी है और इस रफ्तार से आगामी सौ वर्ष में कदाचित् डेढ़-दो करोड़ रोजगार ही उपलब्ध हो सकेंगे । ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार में एक बेरोजगार को वर्ष में सौ दिन रोजगार की गारंटी जख्म पर नमक छिड़कने के समान है । करीब ३५-करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे याने ७-करोड़ परिवार अर्थात् ७-करोड़ रोजगार उपलब्ध होने चाहिए । कहां से आएंगे ।

एक मोटे अनुमान के अनुसार ६०-हजार करोड़ की धन राशि काले धन के नाते चल रही है उसे निकालने की तरकीब, उपरोक्त १०/- टैक्स वाली स्कीम कदापि नहीं हो सकती किंतु वित्त मंत्री जी ने इस ओर आंख मूंद ली । भ्रष्टाचार रूकने की बजाए बढ़ेगा । यथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और बच्चों को दिए जाने वाले आहार की मात्रा व गुणवत्ता भी बढ़ाई जाएगी । किंतु आंगनवाड़ी कर्मी जिसका वेतन मात्र ५-सौ व १-हजार रूपए है उसमें एक पैसा भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई । आहार की खरीद में पहिले ही कमीशन के चलते घटिया सामान खरीदा जाता है अब करीब ६८ हजार केन्द्र और खोले जाएंगे अतः खरीददारी बढ़ जाएगी, तद्नुसार कमीशन व

पृष्ठ ६ का शेष... तक की सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला विश्व का बेजोड़ उद्योग जिसमें उच्चतम गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति के कारण बड़ी मात्रा में कार्य आदेश (Work Orders) पर अभी भी दिन-रात कार्य चल रहा है, ऐसे बिजली उत्पादन की भारी मशीनरी बनाने वाले देश के गौरव स्वरूप उद्योग 'भेल' के १०% विनिवेश के प्रस्तावित सरकारी प्रस्ताव ने न केवल कर्मचारियों बल्कि सभी देशवासियों को अचंभे में डाल दिया है ।

इसके विरोध में हैवी इलैक्ट्रिकल्स वर्कर्स (भामसं.) यूनियन पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग में कार्यरत सभी ५-हजारों कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन राज्यपाल म.प्र. को प्रस्तुत किया है जिसे उन्होंने अपनी टीप से साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित कर दिया है ।

भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा । इसी प्रकार अन्य ग्रामीण योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद वित्त मंत्री जी की ईमानदारी व नेक नियती के चूंकि प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचार रोग ग्रस्त है अतः भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचारी चांदी काटेंगे ।

बजट का मुखौटा अतः जैसा भी हो किंतु इसके नीचे निर्धनता से जर्जर चेहरे की कुरूपता, सामाजिक विसंगतियों तथा विषमताओं को कारी कागजी घोषणाओं से ढांपा तो जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता ।

VISHWAKARMA SANKET
ENGLISH SECTION MARCH, 2005

CENTRAL BUDGET 2005-2006

GLIMPSES OF RECOMMENDATIONS

Concessions to Industry : Lolly-Pop to Agriculture/ Denials/Reduction to the salaried workers

INCOME TAX

Rs. 1 Lakh or below	Nil
Rs. 1 Lakh to 1.5 Lakh	10%
Rs. 1.5 Lakh to 2.5 Lakh	20%
Rs. 2.5 Lakh & above	30%

Exemption for Women upto 1.25 lakh
Exemption for Sr. Citizens upto 1.5 lakh

- MINUS

Standard Deduction withdrawn
Rebate under Sec. 88 goes
Sec. 80L removed
30% Tax on fringe benefits

.1% Tax on Withdrawal of Rs. 10,000 on a Single Day

THEY SAY

P. Chidambaram :

"I am concerned about large transactions especially withdrawal of cash... These cash withdrawals leave no trail and presumably become part of the black economy."

A. B. Vajpayee (NDA):

"It is ridiculous. The provision has made the entire budget exercise a laughing matter."

Gurudas Dasgupta (CPI):

"He (Finance Minister) has made a caricature of himself. I oppose the move."

Anand Sharma (Cong.):

"The party will take up the issue with the Govt."

BHARATIYA MAZDOOR SANGH PRESS RELEASE

IT IS STAGNATING BUDGET

New Delhi : The Central Budget for 2005-06 presented in the Parliament today by the Finance Minister Sh. P. Chidambaram has brought big disappointment to the salaried persons who had demanded I.T. exemption upto 2 lac but the demand has not been accepted. Constitution of 6th Pay Commission was another demand which has also not been accepted. Ceiling on bonus has also not been removed. Number of other expectations of employees from the budget have been dashed down.

Price Rise : Additional cess on diesel & fuel will add in price rise. Aparently one cycle of inflation is visible. The prices of consumer goods are alredy at peak and there will be further rise. There is no proposal in the budget to control price hike.

Employment : There is no concrete proposal on employment generation. Past experience of employment guarantee scheme do not build confidence. The progress on 100 days guaranteed job to one jobless person in a family below the poverty line is not known. There is severe doubt in its implementation because machinery below is not sincere.

Direct Taxes : Giving relief to women and senior citizens and other employees upto 1 lac is not beneficial as standard deductions are withdrawn. Saving is also discouraged as there is no increase in interest rate rather there is proposal for investment of savings under insurance and P.F.

There is no mention of unorganized sector and social security etc. The FDI is not the solution of problems to which the country is confronted.

(A.N.DOGRA)
Secretary

CUSTOM DUTY

Slashed from 20% to 15% or less

EXCISE DUTY SLASHED

A/Cs, Tyres, Polyester Yarn, Refind oil, edible oil and Vanaspati.

COST GO DOWN ON

Refrigerators, Cellphones, PCs, Printers, monitors, Imported Garments, Bakery Products, Tea, imitation, Jewellery

Defence spend down in terms of GDP

Left unhappy with

- Rs.6000 Cr increase in Defence budget
- Lowering of corporate tax
- Reduction in Import Duty
- FDI in mining, trade, pension sector
- Low allocation for social securities

Gold Trading

Mutual Funds allowed to trade in gold in units of Rs100. May have major impact on Saving-Investment Profile

Gender Budgeting

Rs. 14,379 Cr earmarked. All deptt asked for gender budgets

Promises Made

- Rural electrification to cover 1.25 lakh villages in five years
- National Highway Development

Amar Singh (SP):

"Anti farmer & anti-people, benefitting urban upper class."

TUs REJECT LIC WAGE HIKE OFFER

Chennai : The Life Insurance Corporation of India has revised its wage hike offer while retaining the mobility and outsourcing options.

During a fresh round of talks held with the unions on Feb. 3, the management proposed an across the board 12 per cent increase in the total wage bill as on August 1, 2002 from the earlier 11 per cent increase.

The offer also have two-parts. One is the wage hike component. The other involves a productivity linked lumpsum incentive (PLLI) on the performance of the LIC. Unions are not amused by the fresh wage hike offer since the offer still falls short of the one given to the bank employees.

The employees at various centers spontaneously held protest demonstrations to condemn management's rigid attitude.

A mammoth gate meeting was held before Yogakshema on 4th February 2005. Sh. Atul Deshpande, General Secretary NOIW, described the offer as ridiculous and most disappointing. He criticized the management for linking the mobility and outsourcing to the wage revision and condemned the management's attitude delaying the wage settlement without any justification. Shri Atul Deshpande demanded a fresh offer forthwith, guaranteed PLLI and wage settlement before 31st March 2005. He opposed mobility and outsourcing and insisted on guaranteed promotion to the employees and recruitment. He appealed the joint front partners to chalk out the programme for action, including strike to force the management for immediate negotiations and final settlement without delay. The meeting was addressed by S/Shri Venu Gopal and Shri Mishra also.

ICF GOLDEN JUBILEE YEAR NO CONSIDERATION FOR EMPLOYEES

- **Stop Out-sourcing**
- **Drop DAR case be as goodwill**
- **One Addl increment to Employees**
- **Ist Class Privilege Passes during the year**

Chennai : The ICF Administration organised a function to commemorate the Golden Jubilee Year (1955-2005) of Integeral Coach Factory Chennai. Shri R. Velu, Minister of State for Railways (Local MP Shri Kuppuswamy and MLA Shri B. Ranganathan) speaking on the occasion did not touch the employees demands i.e. stoppage of outsourcing, a special increment and 1st class privilege passes for the employees, "Timex" watches to the Pensioners also, as given to the working employees as a gift on the occasion. The employees were dismayed as the administration was not serious about their feelings. However a memorandum was handed over to the minister.

Later on 28-01-05 speaking at the Gate meeting B. Devanand, Dy. Secretary Bharatiya Railway Mazdoor Sangh raised all these issues and hoped that the administration will not lose this opportunity for evolving sweet Industrial Relations by a few goodwill gestures and undoing the wrongs done so far. Shri S. Thirunavukarasu M.P. and Member Railways' Standing Committee assured his help for employees cause. He suggested that a committee of MPs from all parties should examine as to why ICF was outsourcing. The union has also undertaken a signature campaign on these demands.

SHOW THE WAY TO "NOBILITY IN POLITICS" - Kalam

New Delhi : "There should be nobility in politics to bring about a change in the country," the President, A.P.J. Abdul Kalam said at the 51st National Film Awards ceremony here

The President put forward a "difficult mission" for the film fraternity and asked them to take up the challenge of show-casing nobility in politics to help create political heroes in their films.

"If one of you could make four or five films in the next years that shows a boy or a girl taking up politics and bringing about a change through nobility in politics, it could help bring about a change," he said. While pointing out that films were a powerful medium to send out the right message, Mr. Kalam said film-makers should try to project positive aspects.

The President also recited one of his poems, "Rock Walls", that called upon people to allow flowers to grow and rivers to flow instead of building walls of rock around them.

Welcome Delegates to 14th All India Conference Golden Jubilee Year 2005

A.I. CONSUMER PRICE INDEX

Month	Base Year 1960=100	Base Year 1982=100
2004		
Feb.	2485	504
Mar.	2485	504
Apr.	2485	504
May	2504	508
June	2524	512
July	2549	517
Aug.	2574	522
Sep.	2578	523
Oct.	2593	526
Nov.	2588	525
Dec.	2569	521
2005		
Jan.	2593	526

MAKE MARRIAGE REGISTRATION COMPULSORY - NCW

The National Commission for women in its report on "Personal Laws" has suggested registration of all marriages and of imposing ban on bigamous marriages performed after convertion to a faith that allows more than one wife.

RAILWAY BUDGET

• Railway Employees Ignored Again

New Delhi : Laloo Prasad Yadav Railway Minister presented the Railway Budget to the Parliament on Feb 26, 2005. This time too he has not proposed any hike in passenger fares or freight charges nor did he withdraw 7.5% increase in freight introduced in between the two budgets.

The budget is totally silent on the demands of the Railway Employees. There is no provision of any additional facility for the second class passengers.

The concessions announced are insignificant and can be availed in rare cases, as :

- 50% concession for carrying the mortal remains of a person from big hospital.
- 75% concession to rural students appearing for professional exams.
- 100% travel concession for those going for interview for a Govt or state Govt job (Where are the Govt jobs)

• No Additional Facility for Passengers

It talks of 46 new trains, 13 of which will run after gauge convertion (Not before next budget) 23 will be passenger trains of short distance.

The budget reclassifies 4000 commodiuty groups into 80 to make freight calculations easier. Some concession in freight rate has been made for LPG, Kerosene and a few chemicals while there is increase for Fodder, paper, fruits, metals, iron ore and grains.

The promises given in the last budget on providing Environment Friendly Coach Toilet Discharge System and clean stations remain on paper only and A. H. Wheelers still monopolises the Railway Book Stalls.

For the rich there will be Delhi Howrah rail to run at 150 Km per hour, internet booking, coaches to be leased to corrier cos and double decor goods trains much of it may remain unfulfilled atleast by the time the next budget comes.

ECONOMIC SURVEY 2004-2005

The economic survey presented to the parliament on Feb 25, by P. Chidambaram has tried to paint a rosy picture of the economy. It puts GDP growth rate at 6.9% as compared to 8.5% in 2003-2004, Industrial growth at 8.4%, Service sector growth at 8.9%, Exports growth of 23.1% and huge forex reserves.

The annual inflation rate is 6.4% against 5.5% in the previous year, a 5.4 million tonne decline in foodgrain output from the 212 million tonnes in 2003-2004 to 206.4 million tones in 2004-2005. To contain the fiscal deficit is another big headache for the FM.

Another area of worry is lack of job opportunities. Over four crore jobs seekers - 70% of them educated, are registered with employment exchanges, whereas the past record shows 1.03 lakh placements in the first eight months of the year. There has been a decline of jobs by 0.8% in 2003 in the organised sector which contributes a small 7-8% of the total work force.

As against the jobs secenario, centre's expenditure on social sector services had increased by 185% in a decade from Rs.18,240 crore in 1995-96 to Rs52,090 crore in 2004-2005. All this makes India rank eighth among the world's most indebted countries with foreign debt of $113, 590 million.

PRESS NOTE 18 SCRAPPED

Free Hand for Foreign Investors

New Delhi : Prime Minister Manmohan Singh announced the scrapping of Press Note 18. Under Press Note 18, it was mandatory on foreign investors to seek permission of their Indian Joint venture partner before setting up an enterprise manufacturing the same or competitive products. Moreover, there was to be a five-year subset period before the foreign partner could launch competitive products. These provisions were aimed at protecting the domestic industry from unfair competition and prepare itself to adjust to global environment.

Inaugurating the Confederation of Indian Industry Partnership in Kolkata, the Prime Minister acknowledged "we will be doing away with the restrictive provisions of Press Note 18 for all future joint ventures with foreign partners."

To allay the fears of the domestic industry, Commerce and Industry Minister Kamal Nath clarified that the changes in Press Note 18 would not apply to existing joint ventures.

It will now apply only for the same field and not similar or allied fields. Also the onus of proof that the new joint venture would adversely affect would lay equally with the foreign and domestic partners. Till now the onus of proof was only with the foreign partner, Nath said. Later in the day, the govt issued an official notification giving effect to the PM's announcement.

CHILD LABOUR PUT UNDER SSA

Shri Chandrasekhar Rao, Minister of Labour said that the strategy in the 10th Plan is to ensure that all working children below 9 years of age would be directly put into schools under the Sarva Shiksha Abhiyan. Older children in the age group 9 to 14 years will be mainstreamed into formal schools after passing through the bridging school mechanism under the National Child Labour Project Scheme. The scheme initially launched in 12 districts for withdrawing and rehabilitating children working in identified hazardous occupations and processes was extended to 100 disricts in 13 states, during the Ninth Plan. This Scheme has been expended to cover 250 districts in 20 states during the current plan. Mid day meals, stipend, vocational training and health checks are essential components of the scheme.

GOVT ALLOWS PVT TRUSTS TO INVEST IN EQUITY/MUTUAL FUNDS

New Delhi : The government has allowed private sector provident funds to invest up to 5 per cent of their total portfolio (estimated at around Rs 1,35,000 crore) into the equity market. Moroever, they can put in 10 per cent in corporate debt and/or equity-oriented mutual funds. The move is valid from April 1. 2005.

The government also announced new norms for exposure to government securities, specifying that the PF cannot have more than 5 per cent exposure to an individual mutual fund for government securities (or gifts). PF trustees will also be allowed to trade at least 10 per cent of the total portfolio in government securities on marked-to-market basis.

The government also allowed the non-government PFs to invest in term deposits of banks with a maturity period of up to 3 years from next fiscal as against the present norms of investing in 1-year deposits.

Private PFs can also invest in bonds of financial institutions and companies having "investment grade" from at least two credit-rating agencies. The funds can also invest in collateral borrowing and lending operation (CBLO) issued by Clearing Corporation of India and approved by RBI.

These three investments bank deposits, bonds and CBLO - should not exceed 25 per cent of a PF's investments as against the previous limit of 30 per cent. PFs need to park at least 25 per cent of their funds in central government securities and another 15 per cent in either state government securities or debt mutual funds approved by Sebi.

ILLEGAL SECOND WIFE ENTITLED TO MAINTENANCE

New Delhi : The Supreme Court has held that even in the case of an illegal second marraige, the wife is entitled to maintenanace if the husband deserts her.

A Bench, consisting of Justice D. M. Dharmadhikari and Justice H. K. Sema, said :

" bigamous marriage may be declared illegal but it cannot be said to be immoral so as to deny even the right of alimony or maintenance to a financially weak and economically dependent spouse.

Rejecting the husband's contention that there was no question of permanent maintenance to his second wife as the second marriage was declared null and void, the court pointed out that Section 25 of the Act provided for the grant of maintenance while passing any decree in a matrimonial dispute, including the restitution of conjugal rights, judicial separation, divorce, annualment of avoidable marriage or declaring a marriage null and void.

INSURANCE COs HAVE TO RENEW MEDICAL POLICIES : HC

New Delhi : The Delhi High Court said that insurance companies can't refuse renewal of medical insurance policies, on grounds they involved a "higher claim ratio."

Justice Sanjay Kishan Kaul disposing of a case wherein Mukul Lal Duggal's medical insurance with United India Insurance, was refused renewal as the claim was higher than the premium amount.

The court said medical policies were to be renewed at the same term as the previous one, but in cases where high payment was sought, the insurance company could increase the premium to a limited extent.

Duggal had got medical insurance with UII in 1995. He underwent angioplasty in 1998 and 2001. The company paid both claims. When he underwent a bypass surgery in 2002, where he incurred expenses of over Rs 2 lakh, the company refused to pay the claim.

34th NATIONAL SAFETY DAY/WEEK CAMPAIGN

COMMENCING FROM 4TH MARCH 2005

MAKE DISASTER PREPAREDNESS AN INTEGRAL PART OF SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT

- Hold Rallies/Meetings
- Administer Safety Pledge
- Pin NSD Badges on employees
- Organise/practical Demonstration
- Bring an awakening for "Safety First".

NATIONAL SAFETY COUNCIL

Plot No. 98-A, Sector 15, Institutional Area, P.O. Kokan Bhavan, Navi Mumbai-400614

CVC ADVICE CAN BE IGNORED - HC

New Delhi : Madras High Court January 5 judgement by Justice Shivasubramanyam on a writ petition filed by the All India Union Bank Officers Federation challenging the supervisory role of the CVC in cases of official misconduct says.

Any advice or opinion to be sought from the CVC can only be on procedural matters and if any advice is given in the matter of appreciation of evidence, proof of charges, or the quantum of punishment, such advice shall be ignored and not be binding on the disciplinary authority (the concerned Government office). Any regulation to the contrary will be wholly without jurisdiction and inoperative."

We were aware that the CVC's advice is not binding on the disciplinary authority but it is meant to act as a counter-pressure so that the right action is taken against errant officers, says Shankar.

ORDINANCE SETS UP PENSION REGULATOR

New Delhi : The union government has promulgatged ordinance to set up a five-member pension regulator.

The Pension Fund Regulatory and Development Authority has been empowered to promote, develop and regulate the pension sector that is being opened for private funds.

The authority will also frame regulations, disclosure norms, oversee functioning of intermediaries and protect the interest of subscribers of various pension funds.

It will also overlook the new pension scheme that was introduced on January 1 this year which attracted 44,000 central government employees as the subscribers. Further, personnel from six states have also joined this scheme.

The authority will replace the interim regulator appointed by the erstwhile NDA government. The pension regulator will have powers on par with SEBI and Insurance Regulatory Development Authority. Both pension fund operators and subscribers can appeal against a directive of the authority in the Securities Appellate Tribunal which is currently hearing all the cases relating to stock market.

Vast Punitive Powers

The Pension Fund Regulatory and Development Authority has been given a sweeping mandate with search and seizure as well as punitive powers to deal with private pension funds and intermediaries that handle subscribers' money.

The authority has the power to penalize a pension fund up to Rs 25 crore if a fraudulent operation is established. The authority has been empowered to imprison up to 10 years any individual charged with defrauding pension subscribers'.

Further the authority directives cannot be appealed in any civil court including the Supreme Court. Instead, the Securities Appellate Tribunal, which hear capital market-related crimes, can hear the appeals against the authority's decisions.

The authority has also been given powers to conduct investigations into alleged frauds committed by a pension fund or a financial intermediary. If necessary, the authority can even take over the assets - both movable and immovable- in case a pension fund is found guilty of fraudulent transactions.

Apart from sweeping regulatory powers, the authority will also set up a subscriber education and protection fund to support the contributors to pension funds in the event of distress.

BMS DELEGATE MEETS PETITIONS COMMITTEE

Hyderabad : A BMS delegation consisting of Shri S. Mallesham, General Secretary, Shri Ravi Shankar, General Secretary, A.P. Construction Mazdoor Sangh, Shri R.V. Subba Rao, Vice President BMS met the Petetions Committee (Rajya Sabha) at its sitting at Hyderabad on 06-02-05 and presented a memorandum making suggestions for bringing out a comprehensive law covering construction workers.

They observed that the construction workers are covered under various acts like inter-state migrant workmen Act 1979, Contract Labour (R&A) Act 1970, Bonded Labour Act, and Social Security Acts like EPF & ESI, besides other Acts. Dealing with so many authorities results in delay and denial . They suggested formation of a comprehensive law covering all benefits from all Acts under one authority. It was complained against the inaction of the Govt of A.P. and none implementing the welfare measures.

A majority of the Construction Workers work under contractors who complain of insufficient amount in the Contract Award for making proper wage rate and social security measures for the workers. The BMS delegation demanded for appropriate provisions in law to ensure sufficient amount in the Contract awards to meet the requirement of proper wage, and social security measures to workers.

The BMS delegation demanded that it should be ensured that the new law is implemented honestly.

RBI ISSUES NEW NORMS FOR CO-OP BANK MERGERS

Mumbai : Reserve Bank of India (RBI) has said it will allow merger between cooperative banks when the networth of the acquired bank is positive and the acquirer bank assures to protect entire deposits of all the depositors of the acquired bank.

Or else, two banks can merge when the networth of acquired bank is negative but the acquirer bank on its own assures to protect deposits of all the depositors of the acquired bank, the central bank said. The merger can also take place when the networth of the acquired bank is negative and the aquirer bank assures to protect the deposits of all the depositors with financial support from the state government extended upfront as part of the process of merger.

RBI said a cooperative bank can merge only with another cooperative bank situated in the same state or with a cooperative bank registered under Multi-State Cooperative Societies Act.

RBI will examine the scheme with reference to the financial aspects and the interests of depositors, based on the criteria/factors.

ILO CONVENTIONS

LIST OF CONVENTIONS ADOPTED BY ILC SESSIONS (AS IN JUNE 2004)

(Contd from Feb'05 issue)

ILC 29th Session, 1946

C. 77 Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946
C. 78 Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946
C. 79 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946
C. 80 Final Articles Revision Convention, 1946

ILC 30th Session, 1947

❖ C. 81 Labour Inspection Convention, 1947
❖ C. 82 Social Policy (Non-Metropolitan Territories)
C. 84 Right of Association (Non-Metropolitan Territories)
C. 85 Labour Inspectorates (Non-Metropolitan Territories)
C. 86 Contracts of Employment (Indigenous Workers)

ILC 31st Session, 1948

C. 87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948
C. 88 Employment Service Convention, 1948
❖ C. 89 Night Work (Women) Convention, 1948
C. 90 Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948

ILC 32nd Session, 1949

● C. 91 Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised),
C. 92 Accommodation of Crews Convention (Revised),
♦● C. 93 Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1949
C. 94 Labour Clauses (Public Contracts) Convention (Revised), 1949
❖ C. 95 Protection of Wages Convention, 1949
● C. 96 Free-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949
C. 97 Migration for Employment Convention (Revised),
C. 98 Right to Organise and Collective Bargaining

ILC 34th Session, 1951

C. 99 Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture)
C. 100 Equal Remuneration Convention, 1951

ILC 35th Session, 1952

❖ C. 101 Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952
❖ C. 102 Social Security (Minimum Standards)
● C. 103 Maternity Protection Convention (Revised), 1952

ILC 38th Session, 1955

C. 104 Abolition of Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1955

ILC 40th Session, 1957

C. 105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957
C. 106 Weekly Rest (Commerce and Offices)
● C. 107 Indigenous and Tribal Populations Convention.

ILC 41st Session, 1958

❖ C. 108 Seafarers' Identity Documents Convention, 1958
♦● C. 109 Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958

ILC 42nd Session, 1958

❖ C. 110 Plantation Convention, 1958
C. 111 Discrimination (Employment and Occupation)

ILC 43rd Session, 1959

❖ C. 112 Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959
C. 113 Medical Examination (Fishermen) Convention,
C. 114 Fishermen's Articles of Agreement Convention,

ILC 44th Session, 1960

C. 115 Radiation Protection Convention, 1960

ILC 45th Session, 1961

C. 116 Final Articles Revision Convention, 1961

ILC 46th Session, 1962

C. 117 Social Policy (Basic Airms and Standards)
C. 118 Equity of Treatment (Social Security)

ILC 47th Session, 1963

C. 119 Guarding of Machinery Convention, 1963

ILC 48th Session, 1964

C. 120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention,
C. 121 Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980]
C. 122 Employment Policy Convention, 1964

ILC 49th Session, 1965

❖ C. 123 Minimum Age (Underground Work) Convention,
C. 124 Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965

ILC 50th Session, 1966

C. 125 Fishermen's Competency Certificates
C. 126 Accommodation of Crews (Fishermen)

ILC 51st Session, 1967

C. 127 Maximum Weight Convention, 1967
C. 128 Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits

ILC 53rd Session, 1969

C. 129 Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969
C. 130 Medical Care and Sickness Benefits

ILC 54th Session, 1970

C. 131 Minimum Wage Fixing Convention, 1970
C. 132 Holidays with Pay Convention (Revised), 1970

ILC 55th Session, 1970

C. 133 Accommodation of Crews (Supplementary Provisionns) Convention, 1970
C. 134 Prevention of Accidents (Seafarers) Convention,

ILC 56th Session, 1971

C. 135 Workers' Representatives Convention, 1971
C. 136 Benzene Convention, 1971

ILC 58th Session, 1973

C. 137 Dock Work Convention, 1973
C. 138 Minimum Age Convention, 1973

(In next issue and onward)

INTERVIEW OF THE MONTH

PREPARATIONS FOR GOLDEN JUBILEE YEAR CONFERENCE

SHRI RAM DASS PANDE

(Shri Ram Das Pande has been an RSS Pracharak for long. He lived with Late Shri D. B. Thengadiji for more than three decades and assisted him in all sorts of jobs like public relations, publishing etc. He is BMS zonal Incharge for Delhi, Haryana, Punjab, HP, UP, Uttaranchal.)

VS : Ram Das ji, you have been in bed since January 5, How do you feel now ?

RD : I am better, I can stand on my legs now though I still need some support.

VS : Have you started taking solid food ?

RD : No, Doctors have advised me to take liquid only, however instead of taking it through a pipe, I can sip it.

VS : Who gives the final signal to go ahead ? Is it you or some one in the Central Office ?

RD : We have evolved a system of decision making. No individual gives the final word. We sit together, discuss the issue and take collective decision on the issues. In a way all workers are involved in decision making and that makes implementation easy. It becomes a collective responsibility. Whenever one finds a hurdle in the way, we again join our heads and find the way out.

VS : With the all India conference of BMS in the Golden Jubilee Year early next month, don't you feel it isa big set back to preparations ?

RD : We in BMS believe that each one of us does only what is assigned to him by God, neither less, nor more. It is a godly work. "Nar Seva, Narain Seva". He expects only this much from me. so I am here totally demobilised. It is His wish.

VS : But the workers at the grassroot having no past experience look to you for guidance & support in mobilising resources in planning and managing such a huge gathering from all over India.

RD : BMS is not a "Leader Centred" trade union. A worker at the bottom is as important and wise as one at the top. Once it was decided by the February 2002 conference at Thiruvananthapuram (Kerala) that Delhi BMS would host the next conference, efforts were made to involve and mobilise each and every worker in all BMS units in Delhi to get some assignment, Meetings were held at the lowest level to prepare the workers mentally for the challenge. It made us understand the visual they had about various aspects of the conference, the Pandal, the food, the stage, the accommodation and the other services. They gave suggestions many of which we had not thought of such as a worker from the village offered "Salad" for the conference from his fields. Abhyas Vargs (Study Classes) further helped them understand BMS, its way of working and prepared them for sacrifice and total commitment to the cause.

VS : Do you think all this can take practical shape ?

RD : Why not ? you have trust in worker, assign him some responsibility, guide him help him and give him due credit. He will be worth any job. We did the same. Today you ask any worker he will proudly tell you, "Yes, I am fully involved in conference job. I am incharge for water supply or electricity or even for sanitation around toilets.

VS : Still your absence might dishearten them ?

RD : Initially for a few days after I was confined to bed, there was some disappointment. **I talked to them and asked "What is my contribution in all that has been achieved ?** It is you who collected funds, organised meetings and Abhyas Vergs, booked Ram Lila Ground for the venue, sought NOC from the Police, made arrangemnts for food supply and tented accommodation. How does it matter then if I am not there ? I encouraged them that each one of them was capable of doing any thing entrusted to him. I **simply gave them credit for what they had been doing** and they started working with more Vigour and Zeal.

VS : You are an RSS Pracharak. Did it not volunteer to help you in this gigantic job ?

RD : It is not I alone who belong to RSS. Many among us are swayamsevaks. Those outside the trade union know we are doing hard job and are ever willing to volunteer help. But BMS has its own committed cadre, capable of performing any job and accepting any challenge. Even for the purpose of conference we have a team of 250 activists at the top level assisted by a large number of workers. Moreover we go to them for guidence whenever we need. They hold such gatherings every year and have vast experience.

VS : Will the BMS units outside Delhi also share some responsibility ?

RD : State units in the Northern Zone are keen to perform some Aahuti in the Mahayagya, Punjab state unit has offered to meet wheat requirements and similarly the other states also.

VS : Congratulations for all these achievements Mr. Pande.

RD : Why congratulate me ? Congratulate the workers right from the bottom line who are leaving no stone unturned to make this achievement possible.

VS : Thank you for talking to us in spite of your illness.

CHRONOLOGY OF EVENTS (February, 2005)

2-2-05 : King of Nepal SACKS Govt. Declare emergency.

2-2-05 : Govt to Disinvest 10-15% in IA, AI : The Govt would divest 10% to 15% stake in IA, AI during 2005-06 through IPO's. 5% stake may be fixed for employees.

2-2-05 : EPF Interst Rate hiked to 9.5% : The Govt hiked EPF interst rate to 9.5% for the year 2002-03 and 2004-05. The Govt may have to subsidise EPFO to the tune of Rs 700/- crores.

Telecome FDI rased to 74% : The Govt has raised FDI in Telecom from the present 49% to 74%. It claims that National Security has been taken care of.

3-2-05 : India's Per Capita Income Raises by 7.1% : The per capia income calculated at 1993-94 prices stood at Rs11,013 in the previous year. At current prices the per capita income in 2003-04 grew to Rs.20,989 i.e. 7.1% in real terms.

3-2-05 : 12th Finance Commission Recommendation accepted : Govt has acceptd the recommendations of the 12th Finance Commission in Toto. The state will now get 1% higher share at 30.5% in central taxes and pay lower interest at 7.5% on all central loans.

4-2-05 : The MOF and RBI have mooted a plan to double the limit of bank participation in equities from 5% to 10%.

4-2-05 : SBI buys 51% stake in Mauritius Bank : SBI has bought 51% stake in Indian Ocean International Bank in Mauritius. The bank has 7% share in the market with 10 branches & 10 ATMs.

4-2-05 : CVC advice can be Ignored - HC : Justice Shivasubramanyam in a writ petition filed by the All India Union Bank Officers Federation challenging the supervisory role of the Central Vigilence Commissiones in case of officials misconduct says that CVC's advice on evidence proof and punishment shall be ignored & is not binding on the authorities.

5-2-05 : India Economy to grow 6.5% - IMF : India economy would grow by 6.5% as per the International Monetary Fund (IMF). It has warned that huge fiscal defict and public debt may upset it.

8-2-05 : WB demands less Interest on small savings : The West Bengal Chief Minister has told the PM that interest rate on small savings was high which does not go in favour of his states since it borrows maximum loan from it. He sought a decrease in the interest rate.

10-2-05 : Vyas new NCW chairperson : Girija Vyas, the spokes person of the congress party has been nominated to be the chairperson of National Commission for Women. She replaces Poornima Advani who vacated the chair after her tenure ended on Jan. 24. She will hold the rank of a Cabinet Minister.

15-2-05 : Trade deficit widens : During the Period April 04 to January 05, export grew 33% to $6.7 billion whereas imports jumped to 40.4% to touch $9.58 billion. The trade deficit for 10 months was $22.6 billion.

17-2-05 : Delhi Govt moots congestion tax : Park your vehicles away from the congested areas or pay tax for creating congestion.

17-2-05 : The Kyoto (Global Warming) pact takes effect from 16-2-05 : The pact imposes limits on emissions of Carbon dioxide and other gases, scientists blame for rising world temperatures, melting glaciers and rising oceans. India ratified the protocol adopted in 1997, in 2002.

25-2-05 : 100% FDI in Construction : The Govt on Feb 24 allowed 100% FDI in the construction industry through the automatic route. Conditions restructing FDI to a minimum area of 100 acres and 2000 dwelling units are relaxed to 25 acres and 50,000 square metres for construction development projects.

The left is almost silent on the issue since they had already allowed Ciputra & Salim groups of Indonesia for building a project in West Howrah, through Beyond Limit International Ltd. a new company set up in India by them.

25-2-05 : Cancer-causing UK dye spreads Panic : Illegal cancer-causing dye found in a UK made sauce has spread Panic in 15 countries in two continents. Food companies in the US, Canada, Ireland, France, Denmark, Italy, Greece, The Netherlands, Alustralia, Switzerland and Malta are among the 186 firms listed by the sauce manufacturer as its buyers.

RURAL BENGAL SHINING MISLEADING

Kolkata : Lakhs of women in rural Bengal have to travel for kilometres to fetch drinking water. This and other economic indicators collated by the Indian Institute of Economic Studies (IIES) from the National Sample Survery Organisation (NSSO) and census reports blow the "rural Bengal shining" myth perpetrated for years by the ruling Marxists.

Rural Bengal lags behind the rural areas of almost all other states in all economic indices, from consumption of LPG to the state of dwelling units.

Over 75 per cent of the rural households in Bengal don't have their own source of drinking water. Thus the womenfolk of nearly 90 lakh households have to fetch water from tubewells, wells, ponds or streams away from their homes.

According to the latest reports put out by the IIES, consumption by rural households in Bengal was 10.1 per cent lower than the all-India average for rural areas in 2003. Rural Bengal consumed 4.75 per cent less food than the national average (for rural areas), while consumption of milk, eggs, meat and fruits - the strongest indicators of growing incomes - was 4.5 per cent lower.

SUTHERLAND REPORT ON WTO NEEDS CAUTION

Geneva : The report on the Future of the WTO produced early this month by a "consultative board" (established by the director general Supachai Panitchpakdi and chaired by former GATT director general Peter Sutherland) received some cautious and guarded response from many members at an informal meeting at the WTO.

Many members were disappointed by some of the report's proposals including those relating to the establishment of a 30-member "consultative group" of Ministers, which they saw as in effect creating an executive board dominated by major countries. They also did not favour many of the proposals for increasing the powers of the Director General and the Secretariat, or the suggestions to raise the political profile of the WTO through greater involvement of political leaders in the negotiating process.

In his presentation, Sutherland said the report did not deal with Doha agenda. He high-lighted the danger posed by preferential trade arrangements being pursued at the expense of the WTO.

The report, he said, views the consensus principle as being needed at the WTO. But ways should be found to better reach consensus. The EU and the US welcomed the report. On the report's criticism on bilateral, regional and preferential trade agreements, members stressed that such agreements, whilst benefiting their members, should not harm other countries that were not members.

Some countries defended the use of preferences. Kenya said preferences had been used as instruments for development and their use should not be denied on the ground that they are barriers to development. Jamaica also raised concern with the report's remark that GSP beneficiaries become over reliant on preferences at the expense of diversification, commenting that developing countries face handicaps when they try to diversify.

Brazil questioned the proposal to set up a "consultative body" of 30 members, and said there should be clear definition of the role of the Secretariat, which needed more lengthy reflection, and that the WTO should deal with all NGOs and not discriminate between those who relate with the WTO and those who do not. China also said the "consultative body" proposal had to be further studied.

India believed it was more important to focus on the Doha negotiations and thus it would be premature to start any process on the report. It also raised concerns with the plurilateral approach to negotiations (which the report referred to) as it could be used to bring through the side door non-trade issues which had already been rejected.

TERMS OF GLOBALISATION, NEED REVISION - Chidambaram

London : The Union Finance Minister, P. Chidambaram, urged the developed countries to review the current terms of economic globalisation to make the process "more just and more equitable."

Mr. Chidambaram questioned the "terms of engagement" saying they were "heavily weighed" in favour of the developed world. "I urge you to review the process of globalisation." He remarked, in a speech at the Foreign Policy Centre, came ahead of a meeting of the Finance Ministers of seven industrialised countries (G-7).

"The real question is not globalisation. The real question is the terms of engagement in globalisation. As of today, the terms are heavily weighed in favour of the developed countries. Millions of people in developing countries, and in the least developing countries, watch in silence, and with a growing sense of bitterness, that the Age of Prosperity is passing them by. This does not augur well for either globalisation or stability.

POSTMEN "AT HOME" WITH PRESIDENT

New Delhi : The President A.P.J. Abdul Kalam, hosted the customary "At Home" reception at the Mughal Gardens of Rashtrapati Bhavan in honour of the Bhutan King.

For the first time, 150 postmen were invited by the President to the reception to commemorate the 150th anniversary of Indian Posts. They had an exclusive interaction with Mr. Kalam. Appreciating their role in maintaining the lifeline of communication in the hinterland of the country, the President said that in the rapidly changing communication scenario the postman performed the all-important duty of linking rural areas and providing the much-needed connectivity.

"Postmen are good human beings, they should also be righteous people," he told them. Looking at the technological changes, the post office should become a "knowledge centre" to provide villagers information about prices of essential commodities, food grains and weather.

GOVT APPROVES 12th FINANCE COMMISSION

New Delhi : The Cabinet approved the 12th Finance Commission report. It provides for an increase in share of taxes to states from 29.5 to 30.5 per cent. Finance Minister P. Chidambaram said, "the total transfer of taxes and grants to states, as recommended by the Commission, will amount to Rs 7,55,751 crore between 2005 and 2010." Announcing the decision, Chidambaram said Rs 1,408.9 crore will be reimbursed to BSNL.

Postal Regn. No. DL-11430/03-05 (To be Posted on 4&5 March 2005) RN.55626/92

Gujarat Roadways Employees in procession at Ahmedabad

GUJARAT ROADWAYS EMPLOYEES' HOLD MASS RALLY

Ahmedabad : Joint Action Committee comprising of Gujarat S T Mazdoor Mahasangh (BMS), Mazdoor Mahajan and INTUC union in transport organised a mass rally of State Roadways Employees on 21-12-2004 to bring pressure on the State Govt to make payment of the arrears of settlement for the block period 01-08-1997 to 31-07-2002.

A large number of emplyees joined the Maharally. It had its effect. The Govt invited a delegation for negotiations on 25-12-2004 itself, listened to them on their problems and assured that the outstanding issues will be attended to promptly.

Central Govt Employees Rally
DECLARE SIXTH CENTRAL PAY COMMISSION - Uday Patwardhan

New Delhi : The Central Government must listen to the just CRY of its employees and declare Sixth Central Pay Commission before it changes into a THUNDER. It should be constituted during current budget session itself, said Shri Uday Patwardhan, General Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh. He was addressing a huge rally of Central Govt Employees at Jantar Mantar, New Delhi on Feb., 18, 2005.

The recommendations of the Fifth Pay Commission has lost relevance after a lapse of around ten years while many central establishments got wage revision twice during this period.

The BMS leader said that he remembers when a similar rally was helf at this very place to demand merger of DA with pay. The NDA Govt had to accept the demand. 50% DA has been converted into Dearness Pay (DP) for the purpose of grant of DA only. It has not been merged fully for all purposes HRA, CCS etc. We therefore demand of the UPA Govt to merge it with pay atonce for all purposes.

Sh. Uday Rao Patwardhan urged the left trade unions to shun politics and support the demand of 6th Pay Commisssion raised by BMS sincerely in the interest of Central Govt Employees. He declared BMS support to the movement of AI & IA staff in their struggle.

Earlier speaking on the occasion Shri Girish Awasthi Dy. Genl Secy BMS said that convince allowance given to the employees has no equation with what they pay even if they travel by public transport where fares have been increased many fold during the last ten years. Even our demand of Rs 500/- pm convince allowance also needs upward revision. The UPA Govt has denied even the 50% DA merger to Postal Gram Sevaks (ED employees) he said.

On 6th Pay Commission Awasthi ji reminded that the then Prime Minister A. B. Vajpayee had assured formation of 6th Pay Commission after the elections. The assurance given by the then Govt must be fulfilled by the Present Govt.

Sh. D. M. Raodeo Secy Genl. Govt Employees National Confederation said the Govt was only following the policy of NDA Govt on FDI Privatisation (as in ICF Chennai) etc. He referred to the Arbitration award of 6th April 2004 where the Govt was directed to pay HRA at the enhanced rate for the period 1-1-96 to 31-7-1997 which was denied when the new scales were implemented w.e.f. 1-1-1996.

Sh. Vijay Kumar Malhotra Dy. BJP leader in the Lok Sabha addressing the rally endorsed the demand of Govt Employees that Income Tax exemption limit should be raised to 2 Lakh rupees, compassionate appointments should be liberalised and raised to 15% of the vacancies against 5% at present. He assured that they would raise the demand of sixth Central Pay Commission in the parliament.

Others who addressed the rally included Sh. Ram Lubhaya Bawa, Chander Mohan Thapriyal Suresh Kumar, Gaur Gopal Ghosh, B. K. Jaggi, D. Devanand, Sh. Khamborkar, Santosh Singh and others.

A large contengent of workers from ICF Kamgar Sangh Chennai, and also from Defence establishments besides Postal Telecom, Railways had travelled all the way to Delhi.

Printed and Published by Uday Patwardhan and Edited by Prem Nath Sharma for Bharatiya Mazdoor Sangh,
Ram Naresh Bhavan, 2426/27, Tilak Gali, Pahar Ganj, New Delhi-110055 Ph.: 23584212, 23562654, Fax ; 91-11-23582648 &
Printed at Jupiter Printers, 139-B, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110007 Mobile : 9868244372